शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 47 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 47 अंक – 27 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 27 – 4 जुलाई 2022 मूल्य पांच रूपए

आधी आबादी को आधी सुविधा देकर पूरी पर सत्ता का गेम प्लान

- क्या यह आधी सुविधा महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने का प्रयास नहीं है
- क्या यह महिलाओं को समझ नहीं आयेगा कि उन्हें सत्ता की आसान सीढ़ी माना जा रहा है?

शिमला/शैल। यह चुनावी वर्ष है और चुनाव जीतने के लिये कुछ भी करने का अधिकार राजनीतिक दलों का शायद जन्मसिद्ध अधिकार है। सरकार में बैठा हुआ दल इस अधिकार का प्रयोग पूरे खुले मन से करता है और कर्ज लेकर भी खैरात बांटने में संकोच नहीं करता है। इसी परम्परा का निर्वहन करते हुये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सरकार की बसों में महिलाओं को आधे किराये पर आने – जाने की सुविधा प्रदान कर दी है और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू भी हो गया है। जबकि इसी के साथ घोषित न्यूनतम किराया 7रूपये से 5 रूपये करने का फैसला अभी लागू होना है। महिलाओं का बस किराया आधा करने का फैसला धर्मशाला में आयोजित महिला मोर्चा के ''नारी को नमन'' समारोह में लिया गया। इस अवसर पर शायद मुख्यमंत्री भी सभा स्थल तक बस में गये। मुख्यमंत्री जिस बस में गये उसकी चालक भी शिमला से धर्मशाला पहुंची थी जिसे मुख्यमंत्री ने सम्मानित भी किया। महिला चालक का सम्मान शिमला में चल रही सरकारी टैक्सियों में महिला चालकों की भर्ती का फैसला लेना और सरकारी बसों के किराये में 50% की छूट देना महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं और इन्हीं के सहारे सत्ता में वापसी सुनिश्चित मानी जा रही है।

इस परिप्रेक्ष में कुछ सवाल उठ रहे हैं जिन्हें जनत्ता के सामने रखना आवश्यक हो जाता है। इस समय सरकार के सारे निगम बोर्डो में शायद हिमाचल पथ परिवहन निगम ही सबसे अधिक घाटे में चल रही है। शायद अपनी सारी संपत्ति बेचकर भी एक मुश्त अपने घाटे कर्ज की भरपाई नहीं कर सकती। फिर सरकार भी कर्ज के दलदल में गले तक धंस चुकी है। सरकार के फैसले इतने प्रशंसनीय है कि पिछले दिनों एचआरटीसी ने नई बसे खरीद ली जबकि काफी अरसा पहले खरीदी गई बड़ी – बड़ी बसें आज तक सड़कों पर नहीं आ सकी हैं। खड़े – खड़े सड़ रही हैं। ऐसा क्यों हुआ है इसके लिये कोई जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। अब जो किराया सात से 5 रूपये किया गया और महिलाओं को आधी छूट दी गयी है इसका आकलन करने के लिये 2018 से अब तक रहे बस किराये पर नजर डालनी होगी। सितंबर 2018 में न्यूनतम किराया 3 रूपये से 6 रूपये कर दिया गया था। इसका जब विरोध हुआ तो 6 रूपये से 5 रूपये कर दिया। फिर जुलाई 2020 में यही किराया 5 रूपये से 7 रूपये कर दिया। अब इसे फिर से पांच किया जा रहा है। परिवहन निगम इस समय भी 40 से 50 करोड़ प्रति माह के घाटे में चल रही है। कोविड काल में ही 840 करोड़ का घाटा निगम उठा चुकी है। इसे उबारने के लिये सरकार को शायद 944 करोड़ की ग्रांट देनी पड़ी थी। इस तरह परिवहन निगम लगातार घाटे में चल रही है तो सरकार को भी करीब हर माह ही कर्ज लेने की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में क्या निगम या सरकार किसी को कर्ज लिये बिना कोई राहत देने की स्थिति में है।

आज केंद्र से लेकर राज्य तक सभी कर्ज में डूबे हुये हैं और इसी कर्ज के कारण महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। आज जब हर रसोई में इस्तेमाल होने वाले आटा चावल दालें आदि सभी की कीमतें बढ़ गई हैं तो क्या घर संभालने वाली इससे प्रभावित नहीं होगी? क्या उसे नहीं समझ आयेगा कि उसे आधी सुविधा देकर सत्ता पर पूरे कब्जे का गेम प्लान बनाया गया है? क्या तब वह यह नहीं कहेगी कि इस सुविधा के बदले उसके बच्चे को रोजगार दिया जाये। जब उसके पास सिलैन्डर में गैस भरवाने के पैसे नहीं होंगे तो क्या वह खाली सिलैन्डर की आरती उतारकर भाजपा को वोट देंगी?

क्या कांग्रेस में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा बार-बार हो रहे विस्तार से उभरी आशंकाएं

- पुलिस पेपर लीक में क्यों नहीं जारी हुई कथित ऑडियो टेप
- निर्दलीय विधायकों के मामले में भी विधानसभा अध्यक्ष से आगे क्यों नहीं बढ़ रही पार्टी
- राष्ट्रपति चुनाव में अनिल शर्मा का वोट कहां जायेगा?

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पुनर्गठन के बाद राज्य कार्यकारिणी में तीन बार विस्तार हो गया है। इस विस्तार में जिस कद के नेताओं को पद देकर नवाजा गया है उससे न चाहते हुये यही संदेश गया है कि संगठन में नाराज लोगों की समस्या बराबर बनी हुई है। जिससे इस तरह से हल करने के प्रयास किये जा रहे हैं। बल्कि इन प्रयासों के कारण पार्टी नेतृत्व राजनीतिक मुद्दों और जन समस्याओं पर भी पूरा ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है। इस समय कर्ज और बेरोजगारी प्रदेश की सबसे बड़ी समस्याएं बन चुकी है। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर नवनियुक्त उपनेता प्रतिपक्ष हर्षवर्धन चौहान के अतिरिक्त दूसरे किसी नेता ने आवाज नहीं उठाई जबकि अब तक यह मुद्दा जन चर्चा का विषय बन जाना चाहिये था। लगता है कि कांग्रेस नेताओं का ध्यान कैग रिपोर्ट पर नहीं गया है। बेरोजगारी में केंद्र सरकार की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल देश की बेरोजगारी में टॉप 6 राज्यों में शामिल है। ऐसे में पुलिस भर्ती पेपर लीक मामला इस समय का सबसे बड़ा मुद्दा था। जब यह मुद्दा सामने आया और कांग्रेस ने भी इस पर गंभीर चिंता जताई। एक नेता को लेकर यहां तक आ गया कि उसके पास इस प्रकरण से जुड़ी एक ऑडियो टेप है। जिसे शीघ्र ही जारी कर दिया जायेगा। इसी का परिणाम था कि मुख्यमंत्री को यह मामला सीबीआई को देने की घोषणा करनी पड़ी। लेकिन बाद में न तो यह ऑडियो टेप सामने आया और न ही मामला सीबीआई में गया। इसमें मुकेश अग्निहोत्री के अतिरिक्त दूसरे नेताओं की सक्रियता ज्यादा नही बन पायी। इसी दौरान देहरा और जोगिन्दर नगर के दोनों निर्दलीय विधायक भाजपा में शामिल हो गये। दल बदल कानून के तहत यह अयोग्य घोषित हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने इस आशय का आवेदन भी स्पीकर के पास कर रखा है। इस समय राष्ट्रपति चुनाव के परिदृश्य में यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। प्रदेश उच्च न्यायालय में एक याचिका डालकर विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिलाये जा सकते थे कि इसका फैसला 18 जुलाई से पहले किया जाये। लेकिन कांग्रेस अभी भी विधानसभा अध्यक्ष से आगे नहीं बढ़ रही है। इसी तरह भाजपा में विधायक अनिल शर्मा की स्थिति बनी हुई है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा विधायक दल की चंडीगढ़ और बद्दी में दो बैठकें हो चुकी हैं। अनिल दोनों बैठकों से गैरहाजिर रहे हैं। अनिल की नाराजगी को कांग्रेस इस समय भुना सकती थी। अनिल का बेटा आश्रय कांग्रेस के बड़े नेताओं में से है। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर भी खामोश चली हुई है। विश्लेषकों की नजर कांग्रेस की यह चुप्पी इस बात का संकेत मानी जा रही है कि कांग्रेस में कहीं तोड़फोड़ की संभावना तो नहीं बन रही है। क्योंकि लंबे अरसे से ऐसी चर्चाएं चल रही हैं।

राज्यपाल ने शब्दों की भावना को समझने पर बल दिया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला में जसवां-परागपुर विकास परिषद द्वारा आयोजित विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि अक्षर के साथ शब्द की भावना को समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में पुस्तकों और पढ़ने के महत्व पर विशेष बल दिया।

राज्यपाल ने कहा कि वे मोबाइल फोन और टेलीविजन के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन किताबें पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अच्छी किताबों को पढ़ने पर विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को पुस्तकालय में अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हमें किताब जैसा शिक्षक नहीं मिलेगा क्योंकि किताबें हमारी सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक हैं। उन्होंने कहा कि हमारी कथनी और करनी में समानता होनी चाहिए तभी हमारा जीवन सार्थक होगा।

उन्होंने बच्चों के समक्ष अपनी भावनाओं को व्यद्र करते हुए कहा कि उन्हें बच्चों का साथ पसंद है इसलिए वह इस तरह के कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करते हैं। उन्होंने जसवां-परागपुर के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि दूसरों को भी इनसे प्रेरित होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समाज में कई तरह की समस्याएं हैं, परन्तु जो व्यक्ति समस्याओं को पहचान कर इनका समाधान निकाल कर आगे बढ़ता है वह सच्चे अर्थो में समाज सेवा करता है।

परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि वे हर पंचायत में एक पुस्तकालय शुरू करने

के प्रयास करें ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को उनके घर-द्वार के समीप यह सुविधा उपलब्ध हो। उन्होंने कहा कि एक आदर्श समाज स्थापित करने के लिए विभिन्न वर्गो में अच्छी किताबों के प्रति पठन- पाठन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी बच्चों के साथ उनका संवाद जारी रहेगा।

इस संवाद कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जसवां-परागपुर क्षेत्र के विभिन्न गांवों के लगभग 188 विद्यार्थी और अध्यापक शैक्षणिक भ्रमण पर शिमला आये हैं।

इससे पूर्व, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित बाल देसाई ने कहा कि यह अंग्रेजी शिक्षण एवं कम्प्यूटर केन्द्र की ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को कौशल एवं ज्ञान प्रदान कर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने की अभिनव पहल है। उन्होंने शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में जसवां-परागपुर विकास परिषद के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को भविष्योन्मुखी शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह देश के भविष्य से जुड़ा एक प्रेरणादायक कार्यक्रम है।

राज्यपाल का स्वागत करते हुए जसवां-परागपुर विकास परिषद् के अध्यक्ष कैप्टन संजय पराशर ने कहा कि क्षेत्र के 36 गांवों में निःशुल्क कंप्यूटर और अंग्रेजी सीखने के केंद्र खोले गये हैं, जहां करीब 2500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इन केंद्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को किताबें, प्रिंटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

इस अवसर पर विद्यार्थियों और अध्यापकों ने अपने अनुभव साझा किए।

मुख्यमंत्री ने कुल्लू जिले में हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कुल्लू जिले की सैंज घाटी के शैंसर के निकट हुई दुखद बस दुर्घटना पर गहरा दुःख प्रकट किया है। इस हादसे में 12 लोगों की मृत्यु और अन्य यात्री घायल हुए हैं। निजी बस संख्या एच.पी. 30ए-0646 शैंशर से कुल्लू जा रही थी।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पी.एम.एन.आर.एफ.) से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव से व्यक्तिगत रूप से राहत और बचाव कार्यो की निगरानी करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं और अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (एडीएम) कुल्लू पूरी घटना की जांच करेंगे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। जबकि प्रत्येक घायल व्यक्ति को फौरी राहत के रूप में 15,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि घायलों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से मृतकों की आत्मिक शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की।

मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने वित्त आयुक्त राजस्व और मंडलायुक्त मण्डी को तुरंत दुर्घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव अभियान की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं।

आजादी का अमृत महोत्सव फसल बीमा अभियान 1 से 7जुलाई तक

शिमला/शैल। कृषि विभाग के निदेशक डॉ. नरेंद्र कुमार धीमान ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल बीमा के प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 अभियान के अंतर्गत तीसरा फसल बीमा सप्ताह एक से सात जुलाई 2022 तक आयोजित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में चलित वैन रवाना की जा रही है। इस वैन के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना व पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जागरूक किया जायेगा।

उन्होंने कहा कि धान व मक्की का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 15, जुलाई, 2022 तथा टमाटर का बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2022 निर्धारित की गयी है।

उन्होंने कहा कि यह वैन शिमला जिले के अलग-अलग हिस्सों में दो दिनों तक किसानों को जागरूक करेगी। 3 जुलाई, 2022 को जिला बिलासपुर, घुमारवीं व हमीरपुर तथा 4 जुलाई, 2022 को काँगड़ा जिले में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा। उन्होंने कहा कि 5 से 7 जुलाई, 2022 तक सिरमौर जिले के विभिन्न क्षेत्रों राजगढ़, हरिपुरधार, ददाहू से सराहन इत्यादि में किसानों को जागरूक किया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत कृषकों की फसलों के लिए उपलब्ध सभी प्रावधानों, योजना के अंतर्गत सम्मिलित होने के लिए अनिवार्य दस्तावेज, बीमित राशि व निर्धारित प्रीमियम इत्यादि के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। इस अवसर पर कृषि विभाग के अन्य अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जनरल बीमा व कृषि बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।

सच्ची मित्र एवं मार्गदर्शक होती हैं किताबें:राज्यपाल

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर ने रिज मैदान एवं ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में आयोजित शिमला पुस्तक मेले का अवलोकन किया। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी) द्वारा हिमाचल प्रदेश के भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से शिमला में नौ दिवसीय शिमला पुस्तक मेला 25 जून से 3 जुलाई तक आयोजित किया जा रहा है।

इस अवसर पर गेयटी थिएटर में शिमला शहर के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल ने कहा कि किताबें आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं और हमारी सच्ची मित्र, मार्गदर्शक और दार्शनिक के समान होती हैं। उन्होंने कहा कि लेखक के विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वह अपने जीवन के अनुभवों को किताब के माध्यम से व्यक्त करते हैं। इसलिए किताबें हमारी सच्ची मित्र हैं। उन्होंने कहा कि किताबें न केवल हमें सिखाती हैं, बल्कि किताबें पढ़ने का शौक रखने वालों को कभी अकेलापन महसूस नहीं होता।

उन्होंने अपने निजी अनुभव साझा करते हुए कहा कि उन्हें अपने छात्र जीवन से ही किताबें पढ़ने का शौक था और किताबें पढ़ने का शौक उन्हें अपने पिता से मिला। उन्होंने स्कूल और कॉलेज स्तर पर किताबें पढ़कर ज्ञान में वृद्धि की।

राज्यपाल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी में पाठयक्रम की पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि कम हो रही है। उन्होंने कहा कि पढ़ने की आदत डालने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं में यह आदत डालने के लिए उन्होंने इस दिशा में पहल की है। वह स्कूलों का दौरा करते है और छात्रों के साथ कक्षा में बैठते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि वह विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पढ़ोगे तो बढ़ेंगे।

छात्रों द्वारा पूछे गये एक प्रश्न में राज्यपाल ने कहा कि उन्होंने अभी तक कोई पुस्तक नहीं लिखी है लेकिन अब वह आत्मकथा लिखने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह किताबें पढ़ने के लिए समय निकालते हैं। उन्होंने कहा कि वह उपन्यासों को पाठयक्रम में शामिल करने का प्रयास करेंगे।

इससे पूर्व भाषा, कला एवं संस्कृति निदेशक डॉ.पंकज ललित ने राज्यपाल का स्वागत किया।

इस अवसर पर एनबीटी के संपादक, डॉ.ललित किशोर मंडोरा और शिमला के अन्य लेखक भी उपस्थित थे।

इसके उपरांत राज्यपाल ने विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन किया और अपनी रुचि की कुछ पुस्तकें भी खरीदीं। इस पुस्तक मेले में करीब 43 प्रकाशकों के 63 स्टॉल लगाये गये हैं।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा

सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज

विधि सलाहकार: ऋचा

अन्य सहयोगी

राजेश ठाकुर

अंजना

शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान देने की घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का किया धन्यवाद

शिमला/शैल। डा. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल ने विश्वविद्यालय में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसरों के 11 पदों को भरने की मंजूरी के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर और राज्य मंत्रिमंडल का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि पदों का उपयोग कृषक समुदाय को प्रभावी ढंग से सेवा देने के लिए किया जाएगा। प्रोफेसर चंदेल ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों को यूजीसी वेतनमान की घोषणा करने के लिए हिमाचल सरकार का धन्यवाद किया।

प्रोफेसर चंदेल ने बिलासपुर जिला के घुमारवीं में सब ट्रॉपिकल बागवानी के लिए अनुसंधान और विस्तार शिक्षा संस्थान खोलने की संभावना तलाशने के निर्णय की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह का संस्थान, क्षेत्र में सब ट्रॉपिकल बागवानी फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा क्योंकि अनुकूल कृषि-जलवायु परिस्थितियों के कारण व्यावसायिक उत्पादन के लिए बड़ी संख्या में फसलें इस क्षेत्र में उगाई जा सकती हैं। उन्होंने खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री राजेन्द्र गर्ग को विश्वविद्यालय की विशेषज्ञ टीम को कई संभावित स्थलों का दौरा करने और संस्थान खोलने की संभावना तलाशने के लिए स्थानीय प्रशासन को निर्देश देने के लिए धन्यवाद दिया। प्रोफेसर चंदेल ने आश्वासन दिया कि विश्वविद्यालय कृषि समुदाय के विकास के लिए कार्य करता रहेगा।

एनओटीसी के बिना एसआरटी जमा करवाने की तिथि बढ़ाई

शिमला/शैल। परिवहन विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश सरकार ने ट्रांस्पोर्टरों के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग से अनापत्ति कर प्रमाण पत्र (एनओटीसी) के बिना स्पेशल रोड टैक्स (एसआरटी) जमा करवाने की तिथि 31 दिसम्बर, 2022 तक बढ़ा दी है। उन्होंने कहा कि इस तिथि को किसी भी स्थिति में 31 दिसम्बर, 2022 से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।

सरदार पटेल विश्वविद्यालय के 16.18 करोड़ रुपये की लागत के निर्मित दो खण्डों का लोकार्पण किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मण्डी में 16.18 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित हिमाचल प्रदेश के दूसरे विश्वविद्यालय के दो खण्डों का लोकार्पण कर औपचारिक रूप से यह विश्वविद्यालय लोगों को समर्पित किया। सरदार पटेल विश्वविद्यालय मण्डी के नाम से स्थापित इस राज्य विश्वविद्यालय के अन्तर्गत मण्डी, कांगड़ा, चम्बा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू जिला के 141 से अधिक सरकारी और निजी महाविद्यालयों को शामिल किया गया है।

देव सदन मण्डी के सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के अध्यापकों को संशोधित यूजीसी वेतनमान प्रदान करने की घोषणा की और इस सन्दर्भ में एक माह के भीतर अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को उनके क्षेत्र के निकट उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 52 वर्षों के पश्चात राज्य में दूसरा सरकारी विश्वविद्यालय अस्तित्व में आने के उपरान्त आज का यह दिन प्रदेश के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में अंकित हो गया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के गठन के पश्चात 22 जुलाई, 1970 को प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय शिमला में स्थापित किया गया था।

मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों और विद्यार्थियों को इस संस्थान के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूर्ण समर्पण और मिशन मोड पर कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय का नामकरण भारत के लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर किया गया है, जिन्होंने रियासतों का एकीकरण कर अखण्ड भारत के निर्माण में बहुमूल्य योगदान दिया।

जय राम ठाकुर ने कहा कि मण्डी में नए विश्वविद्यालय की स्थापना से प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थी लाभान्वित होंगे, क्योंकि मण्डी हिमाचल के मध्य में स्थित है और अब महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित कार्य के लिए इन पांच जिलों के विद्यार्थियों को शिमला नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में दो विश्वविद्यालय होने से स्नातकोत्तर पाठयक्रमों की सीटों में भी वृद्धि होगी और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आसानी से प्रवेश मिल सकेगा तथा इससे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला का बोझ भी कम होगा।

मुख्यमंत्री ने महाविद्यालय के अपने दिनों को याद करते हुए कहा कि वर्ष 1986-87 में वल्लभ राजकीय महाविद्यालय मण्डी में चार हजार से अधिक छात्र शिक्षा ग्रहण करते थे और आज भी छः हजार से अधिक विद्यार्थियों के साथ यह प्रदेश का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। उन्होंने कहा कि वल्लभ परिसर के निर्माण पर 27 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं और इस वर्ष सितम्बर माह तक इसका निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना के लिए उपयुक्त भूमि का चयन शीघ्र ही किया जाएगा और इस वर्ष जुलाई से मौजूदा परिसर से ही कक्षाएं आरम्भ हो जाएंगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छोटा पहाड़ी राज्य होने के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े राज्यों का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणात्मक शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है और सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने बोर्ड के परीक्षा परिणामों में शानदार प्रदर्शन किया है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधिमण्डल को सम्बोधित किया

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने ओक ओवर, शिमला में भारतीय मजदूर संघ के एक

प्रतिनिधिमण्डल को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी में 50 रुपये की वृद्धि की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों और भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई जाएगी, ताकि विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि संघ की सभी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष मदन राणा ने मजदूर वर्ग के कल्याण के लिए विभिन्न पहल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए संघ के कुछ मुद्दों के शीघ्र निवारण करने का आग्रह किया। इस अवसर पर संघ के महासचिव यशपाल हेटा और अन्य नेता भी उपस्थित थे।

एकल उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने में जनभागीदारी महत्वपूर्णः प्रबोध सक्सेना

शिमला/शैल। अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का उपयोग खत्म करने के दृष्टिगत गठित विशेष टास्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने विभिन्न विभागों तथा जिला उपायुक्तों को एक जुलाई,

2022 से एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर लगाये गये प्रतिबंध का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगी प्लास्टिक स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, कैंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, सजावट में इस्तेमाल होने वाले पोलिस्ट्रीन (थर्माकोल), कटलरी प्लेट, कप, चाकू, ट्रे, गिलास, फोर्क, स्ट्रॉ इत्यादि एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं का निर्माण, यातायात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग एक जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित है। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत शहरी विकास और ग्रामीण विकास विभाग को अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में कूड़े-कचरे के लिए डम्पिंग साइट तथा सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हिमकोस्ट को प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैटेलाइट के माध्यम से डम्पिंग साइट तथा जल स्रोतों के निकट कचरे से सम्बन्धित स्थानों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक अपशिष्ट का समुचित प्रबन्धन किया जाए।

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पादों से होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।

बैठक में निदेशक पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीक ललित जैन, निदेशक शहरी विकास मनमोहन शर्मा, निदेशक ग्रामीण विकास ऋग्वेद ठाकुर, निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग हरबंस सिंह ब्रसकोन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अपूर्व देवगन, वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न जिलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुये।

राष्ट्र पुनर्निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका :गोबिंद ठाकुर

शिमला/शैल। राष्ट्र पुनर्निर्माण में युवाओं की अहम भूमिका है, इसी संकल्प को लेकर भारत स्काउट्स एंड गाइड के छात्रों को भी आगे बढ़ना चाहिए। यह उद्गार शिक्षा मंत्री गोबिंद ठाकुर ने धर्मशाला कालेज के सभागार में रोवर्स रेंजर्स कार्निवल में बतौर मुख्यातिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि स्काउट एंड गाइड के माध्यम से ही युवाओं को सामाजिक प्रकल्पों के साथ जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। इससे युवा शक्ति सही दिशा की ओर भी बढ़ रही है। इससे पहले इससे पहले प्रातःकालीन सत्र में संयुक्त निदेशक अमर बहादुर छेत्री के नेतृत्व में राजकीय महाविद्यालय धर्मशाला के परिसर में स्काउट्स एवं गाइड व राष्ट्रीय झंडा, और मित्र देश नेपाल का झंडा भी फहराया गया ।

विभिन्न राज्यों से आये रोवर्स रेंजर्स व कंटिजेंट इंचार्ज कुनाल पत्थरी माता मन्दिर तक पैदल पहुंचे। रास्ते में एल टी व ए एल टी महारूदरा बोलर, जाहिद कुरैशी ने विभिन्न प्रकार की वनस्पति से अवगत करवाया । रेंजर्स व रोवर्स ने चाय बागानों में विभिन्न प्रकार की चाय की किस्म के बारे में भी जानकारी हासिल की इसके साथ ही शिक्षा निदेशक ने कार्निवल में हिस्सा लेने आए रोवर्स रेंजर्स को स्काउटिंग के नियम व उद्देश्यों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। इस कार्यक्रम के लीडर आफ कार्निवल एवं राष्ट्रीय मुख्यालय के संयुक्त निदेशक अमर बहादुर छेत्री, वोजम के प्रतिनिधि के रूप में एल टी महारुद्रा बोलर, ए एल टी जाहिद कुरैशी, रितेश अग्रवाल, जम्मू कश्मीर से हारुन मलिक, हिमाचल प्रदेश से निकिता शर्मा को आर्डिनेटर मैसेंजर औफ पीस, हरियाणा से शुभम व राहुल, राज्य सचिव डॉ राज कुमार, राज्य आयोजन आयुक्त पंकज गुप्ता, सह आयुक्त सतीश राणा, मीना भट्टी, डॉ. आर सी शर्मा, जिला सचिव जगदीश कौंडल, तरसेम पटियाल, राजेश गुलेरिया, विपन पटियाल अशोक राणा, सतीश कुमार विशेष रूप से हाइक के साथ रहे।

कुपोषित तथा कम वजन वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष फोक्सःडीसी

शिमला/शैल। उपायुक्त कांगड़ा डॉ. निपुण जिंदल ने आंगनबाड़ी वर्कर्स को कुपोषित तथा कम वजन वाले बच्चों के घर माह में दो बार आवश्यक विजिट करने के निर्देश भी दिये गये हैं तथा इसकी रिपोर्ट भी भेजने के लिए कहा गया है। कुपोषित तथा कम वजन वाले बच्चों की स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित की जाएगी इस के लिए सभी स्वास्थ्य विभाग तथा समेकित महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं।

डॉ. निपुण जिंदल ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में कुपोषण मुक्त अभियान की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कुपोषित और कम वजन वाले बच्चों पर विशेष फोक्स किया जा रहा है बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पौषाहार भी वितरित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि पौषहार का सही उपयोग किया जाये इसके लिये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बच्चों के अभिभावकों की काउंसलिंग करने निर्देश भी दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा खंड चिकित्सा अधिकारी प्रत्येक माह की 11 से 14 दिनांक तक कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य को लेकर आवश्यक बैठक आयोजित करेंगे इसमें कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार संबंधी रिपोर्ट भी साझा करेंगे। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि 0 से पांच वर्ष के कुपोषित बच्चों के लिये पौषाहार के लिए आवश्यक सूची भी तैयार करने के लिए कहा गया है ताकि उन बच्चों की डाइट में पौषाहार शामिल किया जा सके। उपायुक्त डॉ. निपुण जिंदल ने कहा कि कुपोषण से प्रभावित बच्चों की सेहत में सुधार की स्थिति की समीक्षा करने के लिए त्रैमासिक बैठक आयोजित की जाएगी।

प्रथम तिमाही में जीएसटी संग्रहण में 67 प्रतिशत की वृद्धि

शिमला/शैल। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इस वित्त वर्ष के प्रथम तिमाही में प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण में 67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 831 करोड़ रुपये के संग्रहण की तुलना में 1385 करोड़ रुपये रहा है। उन्होंने कहा कि जून, 2022 के दौरान राजस्व संग्रहण में पिछले वित्त वर्ष के इसी माह की तुलना में जीएसटी संग्रहण में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि जून, 2021 में 235 करोड़ रुपये जीएसटी संग्रहण किया गया, जबकि जून, 2022 में जीएसटी संग्रहण 372 करोड़ रुपये रहा।

उन्होंने कहा कि यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी सम्बन्धी अनुपालना में सुधार तथा विभाग द्वारा उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से सम्भव हो पायी है। इस वृद्धि का दूसरा मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष की अन्तिम तिमाही में जीएसटी रिटर्न सम्बन्धी दी गई छूट है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न आर्थिक विषमताओं के कारण दी गई छूट से जीएसटी संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में यह कमी दर्ज की गई थी।

विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रिटर्न फाइलिंग में लगातार सुधार, तेज रिटर्न की जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन विभाग के लिए लक्षित क्षेत्र बने हुये हैं। विभाग ने पिछले वर्ष अपने रोड चौकिंग अभियान में किए गए करीब ढाई लाख ई-वे बिल के सत्यापन में और सुधार का लक्ष्य रखा है। विभाग समय सीमा के साथ स्वैच्छिक अनुपालन में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और टैक्स हाट कार्यक्रम के तहत हितधारकों के मुद्दों का निवारण किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने कर अधिकारियों के निरंतर क्षमता निर्माण के लिए हाल ही में जीएसटी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य मंत्रिमण्डल द्वारा राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विभागीय पुनर्गठन को भी सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई है।

खड़े हो जाओ हिम्मत वाले बनो सब जवाबदारीयां अपने सर ओढ़ लो और याद रखो अपने नसीब के रचयिता आप खुद हो। .....स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या यह महंगाई और बेरोजगारी किसी योजना का हिस्सा है

अभी जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने सूचित किया है कि कुछ वस्तुओं पर पांच से 18% तक जीएसटी लगेगा। इन वस्तुओं में खाद्य सामग्री भी शामिल हैं। इन वस्तुओं की सूची जारी हो चुकी है। स्वभाविक है कि इस फैसले के बाद महंगाई बढ़ेगी। डॉलर के मुकाबले रुपया अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच चुका है। आरबीआई के मुताबिक अभी रुपए में और गिरावट आयेगी। विदेशी निवेशकों ने बाजार से अपना निवेश निकालना शुरू कर दिया है। इसमें भी आरबीआई का मानना है कि विदेशी निवेशक आठ लाख करोड़ तक अपना निवेश निकाल सकते हैं। इस निवेश के निकलने का अर्थ होगा कि आने वाले दिनों में और भी भयानक रूप से बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। अभी जून में ही आरबीआई ने अपने अध्ययन में देश के दस राज्यों बिहार, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल, आंध्रप्रदेश, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थितियां चिंताजनक स्तर से भी आगे की हो जायेगी। क्योंकि इन राज्यों के कुल खर्च का 80 से 90% का खर्च केवल राजस्व पर हो रहा है। कैपिटल खर्च के लिए केवल 10% बच रहा है। 31 मार्च 2020 तक की हिमाचल को लेकर आयी कैग रिपोर्ट के मुताबिक यहां भी कुल खर्च का 87% राजस्व पर खर्च हो रहा है। राजस्व के खर्च में केवल वेतन भत्ते पैन्शन और ब्याज की अदायगी ही शामिल रहती है यह सब जानते हैं। केवल ब्याज पर ही 20% से अधिक खर्च हो रहा है। इस समय कुछ राज्यों का आउटस्टैंडिंग कर्ज ही आर बी आई के मुताबिक जी डी पी का 247% से लेकर 296% तक पहुंच चुका है। आर बी आई ने अपने अध्ययन में यह भी स्वीकार किया है कि देश में आर्थिक मंदी का दौर 2018 – 19 से शुरू है जो आज चिन्ता की सारी हदें पार कर गया है। ऐसे में यह सवाल बड़ा अहम हो जाता है कि क्या हमारी सरकारें केंद्र से लेकर राज्य तक इसके बारे में चिन्तित हैं और इससे बाहर निकलने के उपाय गंभीरता से खोज रही हैं। या सत्ता में बने रहने के लिये अपने संसाधनों को बेचने तक आ गयी है?आम आदमी इससे जैसे – जैसे प्रभावित होता जायेगा वह उसी अनुपात में आक्रोशित होता जायेगा। यह तथ्य है इस समय वित्तीय स्थिति पर आम आदमी कोई सार्वजनिक चर्चा न छेड़ दें इसलिए उसके सामने फर्जी मुद्दे खड़े करके उसका ध्यान बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके ताजा उदाहरण नूपुर शर्मा और तीस्ता सितलवाड़ हैं। नूपुर शर्मा पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी इसका प्रमाण है। इसी तर्ज पर सितलवाड़ के मुद्दे पर उच्च न्यायालय से लेकर सर्वोच्च न्यायालय के जजों और पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ घृणास्पद टिप्पणियां सोशल मीडिया के मंचों पर आनी शुरू हो गयी है। लेकिन क्या यह टिप्पणियां महंगाई और बेरोजगारी की पीड़ा से आम आदमी को मुक्ति दिला पायेगी? शायद नहीं। आर बी आई ने यह शायद पहली बार स्वीकारा है कि आर्थिक मंदी 2018 – 19 से शुरू है। स्मरणीय है कि कोरोना का लॉकडाउन और रूस – यूक्रेन युद्ध इसके बाद आये हैं। इसीलिये महंगाई और बेरोजगारी के लिये इन्हें ही दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। इसके लिये सरकार के 2014 से लेकर अब तक के लिये गये कुछ अहम फैसलों पर ध्यान देना होगा। 2014 में सत्ता परिवर्तन के तुरन्त बाद मोदी सरकार ने शांता कुमार कमेटी सार्वजनिक वितरण और कृषि पर बिठाई थी। जिसकी सिफारिशों पर तीन विवादित कृषि कानून आये। 2015 में सरकार प्रापर्टी टैक्स खत्म करके बड़े अमीरों को पहली राहत दी। इसके बाद 2016 में नोटबन्दी लाकर हर आदमी को अपनी जमा पूंजी लेकर बैंक तक पहुंचा दिया। लॉकडाउन में घर से काम में उद्योगों में रोबोट आ गये। विवादित कृषि कानून लाने से पहले श्रम कानूनों में संशोधन करके हड़ताल का अधिकार खत्म कर दिया। अब चुनाव जीतने के लिये प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण से लेकर मुफ्ति योजनाओं का सहारा लिया जा रहा है। इस सब पर गंभीरता और निष्पक्षता से विचार करते हुये आकलन करें कि क्या इसका परिणाम महंगाई और बेरोजगारी नहीं होगा तो और क्या होगा।

नेता संयम बरतें, अवाम को गुमराह न करें

गौतम चौधरी

राष्ट्र विरोधी ताकतों की शह पर आतंकवादी तत्व हमारे पवित्र देश में सांप्रदायिक द्वेष व आतंकवाद की घटनाओं को हवा देते रहते हैं, जिसके पीछे उनकी मंशा देश को अस्थिर करने की होती है। हमारे देश में इन दिनों देश का कानून घृणा फैलाने वालों के साथ सख्ती से निवट रहा है। वहीं कुछ लोग भेड़ की खाल में भेड़िए बन कर समाज में घृणा फैलाने का काम करते कर रहे हैं और कानून के शिकंजे से बचने की पूरी कोशिश करते हैं। वे स्वयं को राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर हैं।

एक नाम है एसक्यूआर इलियास का जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं। इलियास साहब अपने को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं लेकिन भारत में घृणा फैलाने के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। घृणा फैलाने वालों में इनकी सुचि फिलहाल सबसे उपर है।

इलियास साहब महाराष्ट्र के नागपुर में पैदा हुए। नागपुर विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए प्रतिबंधित संगठन – स्टूडेंट इस्लामिक मुवमेंट ऑफ इंडिया, एसआईएमआई की सदस्यता ग्रहण की और इसके ''अंसार'' यानी संरक्षक बन गए। आगे चल कर वे एसआईएमआई के महाराष्ट्र क्षेत्र के पहले अध्यक्ष भी बने। क्षेत्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने वर्ष 1979 नागपुर में होने वाली एसआईएमआई की अखिल भारतीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। आगे चल कर वे एसआईएमआई के केंद्रीय अध्यक्ष भी बने और वर्ष 1980 से लेकर वर्ष 1985 तक इस पद पर बने रहे। यह बताना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एसआईएमआई की हिंसक और षडयंत्रकारी गतिविधियों के कारण वर्ष 2001 में उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया।

भारत की सरकार ने इसे एक आतंकवादी संगठन भी करार दिया था। यह प्रतिबंध आज भी लागू है और इस पर वर्ष 2024 में पुनर्विचार किया जाएगा। यद्यपि अनेकों एसआईएमआई कार्यकर्ता व नेता जेलों में बंद हैं। एसक्यूआर इलियास जैसे नेता अब भी कानून से बचे हुए हैं क्योंकि उन्होंने स्वयं को एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर दिखाया हुआ है।

एसक्यूआर इलियास के एसआईएमआई के साथ संबंध तो हैं ही, उसकी ईरान व पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामिक राष्ट्रों के साथ संदिग्ध दोस्ती भी रही है। इसके कारण भी कानून के तहत कार्रवाई करने वाली संस्था उनके खिलाफ कार्रवाई करने से कतराती रही है। उन्हें डर है कि कहीं भारत का कूटनीतिक संबंध न खराब हो जाए। डॉ. इलियास ने वर्ष 1984 में नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास की सहायता से एक उर्दू मासिक पत्रिका अफकार – ए – मिली शुरू की। वर्ष 1992 में एक अखबार के संपादीक कॉलम में भड़काउ लेख छपने के कारण इसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की गयी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि उसने धर्म और जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने तथा साम्प्रदायिक सद्भावना को प्रभावित करने का कार्य किया है। बात यहीं नहीं रुकी और एसआईएमआई के भूतपूर्व अध्यक्ष केएम बशीर ने इस संपादकीय अंशों को प्रमाण के तौर पर छपवाया तथा पाकिस्तान में स्थित छात्र संगठन इस्लामिक जमियत तलबा के कहने पर देश के विभिन्न हिस्सों में इसकी प्रतियां बटवाई। पाकिस्तान का यह छात्र संगठन सदा से धर्मनिर्पेक्षवाद का विरोध करता रहा है तथा मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे विश्वव्यापी चरमपंथी संगठन की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है।

यहां एक बात बता देना जरूरी होगा कि इसके एक कर्मचारी जिसका संबंध प्रतिबंध एसआईएमआई के साथ था, ने बताया कि डॉ. इलियास हाल के दिनों में एसआईएमआई के खिलाफ लगे प्रतिबंध से संबंधित कोर्ट केस में उनके सलाहकार के तौर पर कार्य कर रहे हैं। सामान्य सिद्धांत है कि बच्चों के चरित्र को देखते हुए उसके मां बाप की प्रकृति और व्यवहार का पता चलता है। जहां एसक्यूआर इलियास ने सिमी के अभियान को चलाने में नेतृत्व प्रदान किया, वहीं उनका बेटा भी पीछे नहीं रहा है। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि उमर खालिद जिस देश के विरुद्ध साजिश रचने जैसे आरोप के अलावा कई अन्य आरोपों का सामना कर रहे हैं उस देश के खिलाफ उनके पिता अपने छात्र जीवन से काम कर रहे हैं। उमर खालिद को भारत के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में वर्ष 2016 में दिल्ली के वसंत कुंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। फिर उसी मामले में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद द्वारा दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में सितंबर 13, 2020 को उन्हें गिरफ्तार किया।

खालिद के पिता जहां देश का एक व्यवस्थित सरकार के खिलाफ मुसलमानों की भावनाओं को भड़काने का कार्य करते रहे हैं वहीं बेटा घृणा फलाने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में सलिप्त रहने का प्रमाण दिया है।

इस्लाम में नेतृत्व की पवित्रता का जबरदस्त खयाल रखा गया है। नेताओं के बारे में कहा गया है कि तुम सभी ग्वाले हो और प्रत्येक ग्वाला अपने – अपने झुंड के लिए जिम्मेदार हो। एसक्यूआर इलियास जैसे स्वघोषित नेता में लोगों को बर्बादी की तरफ ले जाने वाले सभी गुण मौजूद हैं। भारतीय मुसलमानों को एसक्यूआर इलियास जैसे व्यक्ति द्वारा कहे गये प्रत्येक शब्द और उसकी बातों को बिना सोचे – समझे यूं ही नहीं मान लेना चाहिए। इसमें इस्लाम का कम और उनका व्यक्तिगत हित ज्यादा सधता दिखता है। भारत, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों की भूमि है। आइए! हम अपने शांतिपूर्ण वर्तमान और खुशियों से भरे भविष्य को एसक्यूआर इलियास जैसे व्यक्ति की विचारधारा से प्रभावित न होने दें।

कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए डीबीटी योजना की शुरुआत की

शिमला। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) कार्यक्रम का एक हिस्सा होगी, जो सभी प्रशिक्षुओं को सीधे तौर पर सरकारी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। इससे पहले कंपनियां प्रशिक्षुओं को पूरी राशि का भुगतान करती थी और फिर सरकार से उसके लिए प्रतिपूर्ति की मांग करती थी। सरकार डीबीटी योजना के शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से प्रशिक्षुओं के बैंक खातों में अपना योगदान सीधे स्थानांतरित कर देगी, जो छात्रवृत्ति का 25% यानी कि प्रति माह 1500 रुपये तक देय होगा।

केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्किल इंडिया के तहत प्रशिक्षुता को काफी बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षुओं के पहले समूह के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी की आर्थिक सहायता उनके खातों में पहुंच चुकी है। इससे न केवल प्रशिक्षण कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है बल्कि यह कदम हमें स्किल इंडिया की क्षमता को शीघ्र साकार करने के और करीब भी ले जाता है।

भारत के युवाओं को कौशल युक्त, पुनः कौशल से पूर्ण और अधिकतम कौशल युक्त बनाने, प्रति व्यक्ति आर्थिक उत्पादन बढ़ाने तथा राष्ट्रीय अभियानों में उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एक सहभागी आंदोलन में बदलना अनिवार्य है। यह न केवल उम्मीदवारों के समक्ष वास्तविक समय के औद्योगिक वातावरण को उजागर करता है बल्कि उन्हें प्रशिक्षण के दौरान भी अर्थव्यवस्था में योगदान करने का अवसर देता है। इससे सरकार, व्यवसायों और शैक्षिक प्रणालियों के सहयोग से स्थायी कौशल विकास रणनीति बनाकर स्किल इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य कौशल विकास के इस तरह के स्थायी म डल के माध्यम से युवाओं की रोजगार क्षमता को और बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने में मदद करना है।

देश में प्रशिक्षुता व प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 19 अगस्त, 2016 को राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) शुरू की गई थी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य नियोद्राओं को प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने के लिए प्रेरित करना और गहन कौशल विकास के माध्यम से उनकी क्षमताओं को अधिकतम करते हुए सही नौकरी की भूमिका खोजने में सहायता करना है। आज तक, 12 लाख से अधिक प्रशिक्षु विभिन्न उद्योगों से जुड़ चुके हैं।

भारत एक कुशल कार्यबल के निर्माण के उद्देश्य से विभिन्न प्रशिक्षुता सुधारों की शुरुआत के साथ 'विश्व की कौशल राजधानी' बनने का सपना पूरा होने की राह पर है। यह कल्पना की गई है कि आने वाले वर्षों में इन योजनाओं को और बढ़ाया जाएगा तथा सभी अनुबंध डीबीटी अनुबंध होंगे।

गेम-चेंजर के रूप में एनईपी: ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए तैयारी

धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री

जब 2016 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) की शुरुआत की गई थी, तब हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी – देश के सुदूर क्षेत्र में रहने वाली अंतिम महिला तक एलपीजी सिलेंडर के साथ पहुंचना। एक समर्पित कार्यबल और मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ, पीएमयूवाई की सफलता तथा सबसे कमजोर लोगों के जीवन पर इसके महत्वपूर्ण प्रभाव से मुझे भरोसा हुआ है कि हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने में सक्षम होंगे, जिसमें शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की परिकल्पना की गई है, ताकि हमारे छात्र 21वीं सदी की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें।

भारत सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी 50 प्रतिशत से अधिक आबादी की आयु – सीमा 30 वर्ष से कम है। संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश का फायदा स्पष्ट तौर पर दिखता है। लेकिन यह क्षमता हमारे पास हमेशा के लिए नहीं रहेगी। इसका लाभ भी हमें अपने आप ही प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए ठोस प्रयास और नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है। वास्तव में, कुछ विशेषज्ञों का सुझाव है कि भारत 2050 तक एक वृद्ध समाज होगा, जिसमें लगभग 20 प्रतिशत जनसंख्या 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की होगी। इसे सही मानते हुए, एक साधारण गणना बताती है कि हमारे पास युवाओं की क्षमता का पूरी तरह से दोहन करने के लिए लगभग दो दशकों से थोड़ा अधिक समय है, या जिसका प्रधानमंत्री मोदी अमृत काल के रूप में जिक्र करते हैं – स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने से पहले की 25 साल की अवधि। इसलिए हमारी दृष्टि वृद्धि – आधारित नहीं हो सकती, लेकिन हमारे युवाओं की विभिन्न श्रेणियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रणाली में व्यापक बदलाव किये जा सकते हैं।

एनईपी 2020 हमारे देश की यात्रा में ऐसा ही एक परिवर्तन है। प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों में, एनईपी 2020, आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला के रूप में कार्य करेगी। एनईपी पूर्व – प्राथमिक से उच्च शिक्षा के सभी स्तरों पर हमारी शिक्षा व्यवस्था की पुनर्संरचना करती है और एक कौशल और अनुसंधान इकोसिस्टम के साथ इसका पुनर्गठन करती है। यह पहुंच, गुणवत्ता, समानता और किफायती के चार सिद्धांतों पर आधारित है। एनईपी का लक्ष्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के स्थान पर एकल नियामक निकाय के रूप में भारतीय उच्च शिक्षा आयोग (एचईसीआई) को स्थापित करना और उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को वर्तमान के 27.1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2035 तक 50 प्रतिशत करना है। नई शिक्षा नीति सुनिश्चित करेगी कि विनियमन, मान्यता देने, वित्त पोषण और शैक्षणिक मानक – निर्धारण का कार्य स्वतंत्र और अधिकार प्राप्त निकायों द्वारा किया जा रहा है। एनईपी की विभिन्न प्रगतिशील सिफारिशों में शामिल हैं – सभी चरणों में अनुभव से जुड़ी शिक्षा, नवीन और गतिविधि – आधारित शिक्षाशास्त्र, उच्च शिक्षा में प्रवेश/निकास के बहु – विकल्प, विभिन्न संकायों से जुड़ी शिक्षा और एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना आदि। इन व्यापक परिवर्तनों को पूरा करने के लिए नीतिगत सुधारों के साथ भारत की शिक्षा और अध्ययन कार्यक्रमों के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी बहुत जोर दिया गया है।

एनईपी, 21वीं सदी की आकांक्षात्मक शिक्षा प्रणाली का प्रतिनिधित्व करने के साथ – साथ तात्कालिक चुनौतियों की भी पहचान करती है। यह तत्काल सुनिश्चित करने का आहवान करती है कि प्रत्येक छात्र कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त करे। मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता पर 'निपुण भारत' नाम से राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है, ताकि देश का प्रत्येक बालक 2026 – 27 तक कक्षा 3 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक योग्यता प्राप्त कर सके।

नई शिक्षा नीति सभी स्तरों पर सरकारों से यह सुनिश्चित करने का आहवान करती है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए कम से कम कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा/स्थानीय भाषा में हो। हमारी सरकार उच्च शिक्षा में भी स्थानीय भाषाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा इसलिए है, क्योंकि केंद्र सरकार सभी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा मानती है। स्नातक स्तर और डिप्लोमा पाठयक्रमों के लिए स्थानीय भाषाओं में 200 से अधिक तकनीकी पुस्तकें हाल ही में लॉन्च की गई हैं। सरकार स्थानीय और आधिकारिक भाषाओं में इंजीनियरिंग, चिकित्सा और कानूनी विषयों की पाठयपुस्तकों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। प्रवेश परीक्षाओं को भी सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में, इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच में अंग्रेजी अवरोध न बने।

शिक्षक हमारे देश के भविष्य का निर्माण करते हैं। हमें अपने शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए शिक्षण कार्य को फिर से उच्च सम्मान और प्रतिष्ठा देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार, स्वयं – से – सुधार और व्यावसायिक विकास से जुड़े अवसर प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। न केवल स्कूली शिक्षा में, बल्कि हमारे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के संकाय भी नवीनतम तकनीकों और नवाचारों एवं शिक्षाशास्त्र के विभिन्न रूपों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम देश भर में शिक्षक प्रशिक्षण के विश्व स्तरीय केन्द्रों का निर्माण कर रहे हैं। वर्तमान बजट में डिजिटल शिक्षक के लिए भी प्रावधान किया गया है तथा इस उद्देश्य के लिए 6 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

पिछले दो वर्षों का समय अभूतपूर्व रहा है, क्योंकि वैश्विक महामारी का प्रकोप तीसरे वर्ष भी जारी है और इसके परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन में भारी उथल – पुथल के साथ अप्रत्याशित भू – राजनीतिक घटनायें भी सामने आयीं हैं। हालांकि, एकमात्र सकारात्मक बात यह है कि ऐसे कठिन समय नवाचारों को जन्म देते हैं। अगर हम अपने आस – पास देखें तो हमारे युवाओं में कुछ नया करने की भावना और बढ़ी है। कोविड – 19 के दौरान हमारे शैक्षणिक संस्थानों में कई नए मॉडल सामने आए हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि विश्व – स्तरीय प्रौद्योगिकी समानता और क्षमता प्रदान करने वाली होती है। केंद्रीय बजट में शिक्षा प्रसार के लिए 200 नए टीवी चैनलों का प्रावधान किया गया है और पांच वर्षों की अवधि के लिए लगभग 930 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की दहलीज़ पर है। हालांकि हम पहली दो क्रांतियों में बहुत पीछे रह गए और हमने तीसरी क्रांति के साथ चलने की कोशिश की, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हम चौथी क्रांति में आगे – आगे चल रहे हैं। एआई, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन जैसी उभरती प्रौद्योगिकियां पर्याप्त अवसरों के साथ – साथ चुनौतियां भी पेश करती हैं, क्योंकि इनसे कई पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो जातीं हैं। लेकिन यह मनुष्यों, मशीनों और एल्गोरिदम के बीच श्रम के एक नए विभाजन से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं को भी सामने लायेगी। इसलिए श्रमिकों के लिए कौशल विकास करने या फिर से कौशल प्राप्त करने से जुड़ी अवधि छोटी हो गई है और इस विषय पर तुरन्त कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर आधारित विभिन्न पहलों की शुरुआत को सुनिश्चित किया जा सके।

21वीं सदी ज्ञान की सदी है। भारत सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समृद्ध भविष्य की ओर ले जाने में एक ज्ञान – आधारित समाज को (कप्तान' बनने का स्वाभाविक लाभ मिलता है। मेरा मानना है कि संविधान के बाद, एनईपी 2020 एक ऐसा दस्तावेज है, जिसे देश भर में कई स्तरों पर विचार – विमर्श, चर्चा और भागीदारी के संवादों के बाद अंतिम रूप दिया गया है। संविधान की तरह, एनईपी 2020 हमें दशकों की दुविधा और संदेह से बाहर निकालेगी और विचार, आत्मा, बुद्धि तथा कर्मो के सन्दर्भ में भारतीय होने का गर्व पैदा करेगी। यह समग्र विकास और पूर्ण मानवीय क्षमता को प्राप्त करने के लिए छात्रों, शिक्षकों, माता – पिता और समाज को एकीकृत करती है।

हमारे युवा न केवल नौकरी चाहने वाले बल्कि नौकरी देने वाले के रूप में भी काम करने की इच्छा रखते हैं। यदि हम उन्हें आज का गुणवत्तापूर्ण ज्ञान और कौशल प्रदान कर सकते हैं, तो हम भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने में सक्षम होंगे, जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था। एनईपी 2020 को बस यही करने के लिए तैयार किया गया है। हम अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहे हैं, ऐसे में यह राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारा योगदान होगा।

हिमाचल प्रदेश में 93.05 प्रतिशत परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत क्रियाशील घरेलू कनेक्शन प्रदान

जनजातीय जिला किन्नौर व लाहौल स्पीति सहित चार जिलों में शत – प्रतिशत कवरेज का लक्ष्य हासिल

भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टशीगंग गांव में घरेलू नल कनेक्शनों से पहुंचाया पानी

हर घर नल से जल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आरम्भ किए गए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के चार जिलों ऊना, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के हर परिवार को क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान करने का शत – प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के साथ ही राज्य में अब तक 93.05 प्रतिशत परिवारों को इस मिशन के तहत क्रियाशील घरेलू कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए जा चुके हैं।

चार जिलों में शत – प्रतिशत लक्ष्य हासिल

क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान करने का शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाले राज्य के चार जिलों में लाहौल स्पीति, ऊना, किन्नौर और चंबा शामिल हैं। प्रदेश के 24 खंडों, 2331 ग्राम पंचायतों और 14,661 गांवों को जल जीवन मिशन के तहत अब तक पूरी तरह से कवर किया जा चुका है। राज्य में पिछले अढ़ाई वर्षों के दौरान 8.44 लाख घरों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं जबकि पिछले 72 वर्षों के दौरान केवल 7. 63 लाख घरों में ही नल कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

4418.37 करोड़ रुपये की राशि आवंटित

मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार की ओर से राज्य को अब तक 1,028.43 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि सहित कुल 4418.37 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

किन्नौर में 22763 घरों को जलापूर्ति

जनजातीय जिला किन्नौर में 22763 घरों वाली 411 बस्तियों को जलापूर्ति की गई है। जिला में जेजेएम के तहत 219 योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी, जिसमें से 155 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 183 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की 55 योजनाओं का कार्य प्रगति पर है।

लाहौल स्पीति जिला में 7284 घरों में जलापूर्ति

लाहौल स्पीति जिला में 7284 घरों वाली 364 बस्तियों को जलापूर्ति की गई है। जिले में जेजेएम के तहत 7 योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिला में जेजेएम के तहत निष्पादित किए जा रहे कार्यों की कुल अनुमानित लागत 122 करोड़ रुपये है।

आकांक्षी जिला चंबा में शत – प्रतिशत कवरेज

चंबा जिला को नीति आयोग द्वारा एक आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है। इस जिले के जनजातीय उप – मंडलों पांगी और भरमौर सहित जिला में 420 करोड़ रुपये लागत की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। चंबा में 265 योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। जिला के सभी 121752 घरों में क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान कर 100 प्रतिशत कवरेज के लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है। जेजेएम के अन्तर्गत इस जिला में योजना के स्रोत चयन, योजनाओं के निष्पादन, फील्ड जल परीक्षण में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जिले की सराहना की गई है।

ऊना जिला में भी लक्ष्य हासिल

ऊना जिला में भी जेजेएम के तहत 196 करोड़ रुपये लागत की 15 योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। जिला में जेजेएम के अन्तर्गत सभी 115949 घरों में क्रियाशील नल कनेक्शन प्रदान करने का शत – प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया गया है।

देश के सबसे ऊंचे गांव में पहुंचा पानी

स्पीति घाटी में समुद्र तल से 15,256 फीट की ऊंचाई और भारत – चीन सीमा से 10 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव टशीगंग में भी क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान कर पानी पहुंचाया गया है। प्रदेश का यह गांव भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है।

पेयजल की मात्रा व गुणवत्ता में भी हिमाचल सर्वश्रेष्ठ

भारत सरकार की निरीक्षण एजेंसी द्वारा वर्ष 2020 – 21 के दौरान किए गए आकलन में विभिन्न राज्यों में उपभोद्दा स्तर पर उपलब्ध पेयजल की मात्र और गुणवत्ता की विभिन्न मापदंडों पर जांच की गई, जिसमें हिमाचल प्रदेश को समग्र कार्यक्षमता में सर्वश्रेष्ठ आंका गया है। राज्य देशभर में अग्रणी है और प्रदेश का समग्र प्रदर्शन उन राज्यों से भी बेहतर है, जिनका नल उपलब्ध करवाने का प्रतिशत हिमाचल प्रदेश से अधिक है।

समय की हुई बचत

उपभाक्ता स्तर पर गुणवत्तापूर्ण जलापूर्ति की उपलब्धता ने जीवन स्तर और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार किया है। प्राकृतिक स्रोतों से पानी की निर्भरता कम हुई है, जिससे लोगों के समय में बचत हुई है और वे अब अपने समय को आजीविका कमाने में उपयोग कर रहे है। राज्य की महिलाएं अब बागवानी, कृषि और हथकरघा जैसी गतिविधियों में शामिल हो रही हैं। जल जीवन मिशन जनजातीय क्षेत्रों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में भी सहायक सिद्ध हो रहा है।

महिला अधिकारों के मार्ग पर जहां पश्चिम के पिछड़ रहे कदम, वहीं भारत दिखा रहा आगे की राह

– स्मृति इरानी –

पश्चिमी देशों में गर्भपात पर लगभग पूर्ण प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया और सड़कों पर चिंतित करने वाले विरोध प्रदर्शनों व हंगामे के बीच, गर्भावस्था की समाप्ति पर भारत का उदार रुख बहुत सुकून देने वाले देश के रूप में है। व्यावसायिक सरोगेसी पर रोक और शादी के लिए पुरुषों और महिलाओं की उम्र को बराबर करने के प्रस्ताव के साथ, भारत प्रजनन स्वायत्तता की रक्षा करने वाले अग्रणी देशों में शामिल है।

भारत की संवैधानिक लोकनीति, अनुच्छेद 21 के माध्यम से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। गर्भपात या गर्भावस्था की समाप्ति एक महिला के आत्मनिर्णय का विशेषाधिकार है। विशुद्ध रूप से शारीरिक संरचना के कारण, महिलाओं के लिए बच्चे को जन्म देना उनकी नियति है– सामाजिक–सांस्कृतिक स्थिति भी महिलाओं को बच्चे के पालन–पोषण का लगभग सम्पूर्ण भाग, जो समानुपातिक नहीं है, की जिम्मेदारी देती हैं।

गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति (संशोधन) अधिनियम, 2021 सही दिशा में उठाया गया कदम है। यह सुनिश्चित करता है कि निकट भविष्य में बच्चे को जन्म देने वाली महिलायें अपने घरों में नए जीवन का स्वागत करने के लिए आत्मनिर्णय करें। अधिनियम के तत्वावधान में, गर्भपात 24 गर्भावधि सप्ताह तक करवाया जा सकता है, यदि मां के जीवन के लिए जोखिम, मानसिक पीड़ा, दुष्कर्म, अनाचार, गर्भनिरोध विफलता या भ्रूण असामान्यताओं के निदान आदि कारण मौजूद हों। अधिनियम एमटीपी अधिनियम, 1971 द्वारा तय की गयी 20 सप्ताह की चुनौती से आगे जाता है और स्वास्थ्य व प्रजनन विज्ञान के क्षेत्र में हुई प्रगति को स्वीकार करता है। यह उन देशों की तुलना में एक उदार उपलब्धि है, जहां यौन शोषण या अनाचार की सबसे अधिक पीड़ादायक परिस्थितियों के बावजूद गर्भधारण के बाद से गर्भपात की अनुमति नहीं है।

एमटीपी अधिनियम, 2021 इसे तैयार व अंतिम रूप देने वालों के अंतर्ज्ञान और दूरदर्शिता को प्रमाणित करता है। बच्चों के लिए तत्परता और उनकी वांछनीयता निर्णायक रूप से माताओं, परिवारों व बच्चों(तीनों के जीवन पथ को आकार देती हैं। अवांछित गर्भधारण अप्रत्याशित रूप से माता–पिता के जीवन से जुड़े विकल्पों को कम कर देता है– विशेष रूप से माताओं के परिप्रेक्ष में– और उनके मानसिक स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास को भी प्रभावित कर सकता है।

इसके अलावा, जन्म लिए अवांछित बच्चों को कम अवसरों का सामना करना पड़ सकता है। उदाहरण के तौर पर, डब्ल्यूएचओ बच्चों के 'वांछित' रूप में पैदा होने की संभावना को उनकी शिक्षा में माता–पिता के अधिक निवेश से जोड़ता है। इसलिए एमटीपी अधिनियम माताओं को अवांछित गर्भधारण के भावनात्मक और वित्तीय बोझ से मुद्र करता है।

मौजूदा कानून और नीति–निर्माताओं ने बड़ी कुशलता से प्रजनन विकल्प को जीवनचक्र से जोड़ दिया है। चूंकि प्रजनन क्षमता, बच्चे को जन्म देना और बच्चे का पालन–पोषण स्पष्ट रूप से विवाह से जुड़ा हुआ है, इसलिए महिलाओं के लिए कानूनी तौर पर विवाह योग्य आयु बढ़ाने का प्रस्ताव करके, नीति–निर्माता गर्भावस्था में देरी करने वाले स्वागत योग्य परिवर्तनों की शुरुआत कर रहे हैं।

बाल विवाह निषेध (संशोधन) विधेयक, 2021 महिलाओं की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रयास करता है। यह विधेयक, डब्ल्यूएचओ द्वारा उद्धृत विशेषज्ञता और साक्ष्यों के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 10 से 19 वर्ष की आयु की किशोर माताओं को 20 से 24 वर्ष की आयु की महिलाओं की तुलना में एक्लम्पसिया, प्यूपरल एंडोमेट्रैटिस और प्रणालीगत संक्रमण के उच्च जोखिम का खतरा होता है। ऐसी माताओं से पैदा होने वाले बच्चों को जन्म के समय कम वजन, समय से पहले प्रसव और गंभीर नवजात स्थितियों के अधिक जोखिम का सामना करना पड़ता है।

यह ध्यान देने योग्य है कि एनएफएचएस–4 (2014–15) से एनएफएचएस–5 (2019–21) के बीच बच्चे पैदा करने की सीमा या अंतराल के संदर्भ में परिवार नियोजन की अधूरी आवश्यकता 12.9 फीसदी से घटकर 9.4 फीसदी रह गई। हालांकि, एकल मानक पर, एनएफएचएस–5 के समय 15–19 वर्ष की आयु की लगभग 7 प्रतिशत महिलाएं पहले से ही मां थीं या गर्भवती थीं, जो एनएफएचएस–4 के 7.8 प्रतिशत से मामूली गिरावट को दर्शाती है। ऐसी युवा माताओं को दूध पिलाने की प्रथाओं और बच्चों की देखभाल के बारे में बहुत कम जानकारी होती है, जिससे बच्चों के स्टंट या वेस्टेड होने की संभावना बढ़ जाती है। एमटीपी अधिनियम, 2021 और पीसीएमए विधेयक, 2021 को मिलाकर– यदि अधिनियमित किया जाता है – तो यह कम उम्र में विवाह, जिसके परिणामस्वरूप जल्दी गर्भधारण और खराब मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिणाम सामने आते हैं, के दुष्चक्र को समाप्त कर सकता है।

एक नीतिगत नवाचार, जिसका श्रेय सरकार को अपेक्षाकृत बहुत कम मिला है, वह है–सरोगेसी बाज़ारों को महत्वहीन बनाना, जिसमें 'किराए पर गर्भ लेने' की अनुमति दी गयी थी। वैश्विक असमानताओं को देखते हुए, भारत सरोगेट माताओं के लिए एक आकर्षक 'बायोमार्केट' बन गया था। गरीब भारतीय महिलाओं के शरीर ग्लोबल नॉर्थ के निवासियों के लिए 'जैविक रूप से उपलब्ध' हो गए थे, जिससे मातृत्व का व्यावसायीकरण हुआ, महिलाओं को विशिष्ट वस्तु के रूप में देखा गया और उनकी प्रजनन क्षमता में कमी आई। भारत को 'बेबी फैक्ट्री' कहा जाने लगा, कई मामलों में बच्चों को छोड़ दिया गया, सरोगेट का शोषण किया गया और मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। एक ऐसा देश, जहां माताओं को सम्मान देने की लम्बी सांस्कृतिक परम्परा रही है, लापरवाह व्यावसायिक सरोगेसी की पूरी व्यवस्था सांस्कृतिक लोकाचार के विपरीत प्रतीत होती है।

इस विसंगति का जवाब देते हुए, सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 ने व्यावसायिक सरोगेसी के स्थान पर नैतिक, परोपकारी सरोगेसी को पेश किया। यह अधिनियम देश में सरोगेसी का लाभ उठाने को लेकर उन जोड़ों पर प्रतिबंध लगाता है, जो भारतीय मूल के नहीं हैं। यह अधिनियम केवल प्रमाणित, चिकित्सा कारणों से स्थानीय लोगों को ही इसका लाभ उठाने की अनुमति देता है, जिनके लिए गर्भकालीन सरोगेसी की आवश्यकता मौजूद है। एमटीपी अधिनियम, सरोगेसी अधिनियम और पीसीएम (संशोधन) विधेयक, 2021 सामूहिक रूप से नारी शक्ति को नया अर्थ देते हैं।

इस सक्षम राजनीतिक–कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत, सरकार ने ऐसी नीतियां बनाई हैं, जो महिलाओं द्वारा तय किए गए विकल्पों और निर्णयों का सम्मान करने के लिए मौजूद हैं। आयुष्मान भारत–जन आरोग्य योजना (पीएम–जेएवाई) के तहत, प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है और इसमें प्रसूति व स्त्री रोग से संबंधित पैकेजों की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश की जाती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) गर्भावस्था से पहले और बाद में मजदूरी के नुकसान की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करती है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) गर्भवती महिलाओं के वित्तीय बोझ को कम करते हुए, प्रत्येक महीने के 9वें दिन गर्भवती महिलाओं को मुफ्त प्रसवपूर्व देखभाल की सुविधा प्रदान करता है।

सरकार न केवल महिलाओं के लिए प्रजनन विकल्पों के खर्च को कम करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है, बल्कि जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव के माध्यम से सुरक्षित मातृत्व को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, लक्ष्य जैसी योजनाओं के तहत प्रसव के दौरान गुणवत्तापूर्ण व सम्मानजनक देखभाल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप संस्थागत प्रसव में कई गुना वृद्धि हुई है, जो एनएफएचएस–4 में 79 प्रतिशत से बढ़कर एनएफएचएस–5 में लगभग 89 प्रतिशत हो गई है। राष्ट्र के लिए अंतिम पुरस्कार माताओं की लंबी उम्र है, जो मातृ मृत्यु अनुपात (एमएमआर) में गिरावट से परिलक्षित होती है। मातृ मृत्यु अनुपात 2011–13 में 167 प्रति लाख जीवित जन्मों से घटकर 2019 में 103 प्रति लाख जीवित जन्म रह गया है।

वर्तमान सरकार अपनी बहुरूपी बेटियों को सर्वोच्च सम्मान देती है, जो अपने जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में न केवल प्यार करने वाली माताओं के रूप में, बल्कि ईमानदार छात्राओं, मूल्यवान कर्मचारियों और साहसी उद्यमियों के रूप में भी कार्य करती हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान का आहवान यह सुनिश्चित करने के लिए है कि लड़कियों का जन्म और पालन–पोषण प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाओं के बेहतर लिंगानुपात के रूप में हो। उज्ज्वला और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं से घर की महिलाओं के समय की बचत हुई(इनसे ईंधन की लकड़ी या पानी इकट्ठा करने की कड़ी मेहनत से राहत मिली, ताकि वे अन्य लाभकारी गतिविधियों में भाग ले सकें। मुद्रा योजना ने इच्छुक महिला उद्यमियों को बिना गिरवी के ऋण की सुविधा दी है और एक अन्य योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने महिलाओं के लिए सब्सिडी की उच्च मात्रा पर जोर दिया है।

पश्चिमी देश गर्भपात के अधिकारों में कटौती कर रहे हैं, जबकि भारत गर्भपात की मान्य सीमा का विस्तार कर रहा है। जहां मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में दुनिया के बाकी हिस्सों में दबे स्वर में बातचीत की जाती है, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस मुद्दे को अपने संबोधन में शामिल किया, जिसे 1.3 अरब भारतीय ध्यान से सुन रहे थे। तीन तलाक को गैरकानूनी घोषित करके, सरकार ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा सामना की जा रही असुरक्षा की निरंतर स्थिति को खत्म किया है। सरकार ने विवाह योग्य आयु को संशोधित करने का प्रस्ताव देकर पुरुषों और महिलाओं को समान व निष्पक्ष मानकों पर रखा है। वर्तमान सरकार ने नीति–निर्माण में बहुत सावधानी से कर्तव्यनिष्ठा का संचार किया है–इस आशा के साथ कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भारत की माताओं और बेटियों के जीवन को बेहतर बनाएगी। पश्चिमी देश हालांकि पीछे हट रहे हैं, भारत दुनिया को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए एक प्रगतिशील समाज का मार्ग दिखा रहा है।

पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बड़ी चुनौती होगा जलवायु परिवर्तन का मुद्दा:ललित जैन

शिमला/शैल। जलवायु परिवर्तन के मुद्दे वैश्विक चिंता का विषय हैं, इसलिए वे हमारे पर्वतीय पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं क्योंकि पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दर्शाने में पर्वतों की विशेष भूमिका होती है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में 51 मिलियन लोग हैं जो पहाड़ी कृषि का अभ्यास करते हैं और जिनकी जलवायु परिवर्तन के कारण भेद्यता बढ़ने की उम्मीद है। पिछले कुछ वर्षों में तेजी से विकास ने पूरे हिमालयी क्षेत्र के पर्यावरण और पारिस्थितिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि तापमान में वृद्धि के साथ–साथ पर्यावरणीय गिरावट के परिणामस्वरूप ग्लेशियरों का तेजी से क्षरण होगा, जो हमारे लिए उपलब्ध मीठे पानी का एक महत्वपूर्ण भंडार है।

ललित जैन, निदेशक (पर्यावरण, विज्ञानं और प्रौद्योगिकी) और सदस्य सचिव (Himachal Pradesh Council for Science & Technology, Environment) ने एक दिवसीय कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए बताया कि पर्यावरण क्षरण, जलवायु परिवर्तन और क्रायोस्फीयर जैसे क्षेत्रें पर प्रभाव के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए जिसमें बर्फ और ग्लेशियर, पानी, कृषि, वन शामिल हैं।

सामान्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज (IISC बैंगलोर) के सहयोग से एचपी काउंसिल फॉर साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के तत्वावधान में एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया। जलवायु परिवर्तन और पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव पर नीति निर्माताओं और प्रशासकों ने आज होटल हॉलिडे होम, शिमला में कार्यशाला की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त पर्यावरण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी) प्रबोध सक्सेना ने की। प्रबोध सक्सेना ने कहा कि यह हमारे लिए समय और अवसर है कि हम आपकी सलाह के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन केंद्र की संकल्पना करते हुए निर्धारित आदेश को पूरा करें और अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ, स्थिर और टिकाऊ वातावरण प्रदान करने के लिए काम करें। भविष्य की योजनाओं और नीतियों को तैयार करने में इस महान सभा की सलाह और सुझावों से हिमाचल सरकार निश्चित रूप से लाभान्वित होगी मुझे उम्मीद है कि हम सभी इस दिशा में एक साथ काम करेंगे ताकि इस हिमालयी राज्य में बदलती जलवायु के लिए तैयार करने के लिए विभिन्न अनुकूलन और शमन रणनीतियों को विकसित करने के लिए एक विश्वसनीय वैज्ञानिक डेटाबेस तैयार किया जा सके।

कार्यशाला की व्यापक संरचना की जानकारी देते हुए, डॉ आर कृष्णन, निदेशक, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे ने सामान्य जलवायु परिवर्तन परिदृश्य के बारे में हिंदू कुश हिमालय पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर प्रतिभागियों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि 1901–2014 के दौरान एचकेएच में वार्षिक औसत सतह–वायु–तापमान में लगभग 0.1 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से वृद्धि हुई, 1951–2014 के दौरान प्रति दशक लगभग 0.2 डिग्री सेल्सियस की तेजी से वार्मिंग की दर के साथ। भारतीय विज्ञान संस्थान (बीएससी) बैंगलोर के दिवेचा सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुलकर्णी ने प्रतिभागियों को हिमाचल के विशेष संदर्भ में हिमालयी क्रायोस्फीयर और सामान्य रूप से हिमालयी क्षेत्र में पानी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से अवगत कराया। डॉ.अनिल कुलकर्णी ने कहा कि तापमान में 2.6 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ, हिमनद सदी के अंत तक हिमाचल प्रदेश में 79 प्रतिशत बर्फ खो देंगे और तापमान में 4.1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ ग्लेशियर अंत तक 87 प्रतिशत बर्फ खो देंगे।

इसके अलावा, डॉ.जे.सी.राणा, कंट्री डायरेक्टर, एलायंस ऑफ बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल और सीआईएटी–क्षेत्र–एशिया ने हिमालयी क्षेत्र में जलवायु भेद्यता को कम करने के लिए आजीविका, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार के लिए कृषि–जैव विविधता की मुख्यधारा पर चर्चा की। अपूर्व देवगन, आईएएस, सदस्य सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इज़राइल यात्रा पर अपने अनुभव साझा किए और बताया कि कैसे विभिन्न प्रथाओं को अपनाया जा रहा है जो राज्यों के दृष्टिकोण से प्रासंगिक हैं। हिमकोस्टे के प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. एस.एस. रंधावा ने दर्शकों को संवेदनशील बनाने के लिए कार्यशाला के दौरान हिमालयी बर्फ और ग्लेशियरों पर किए गए कार्यों पर अपने हालिया निष्कर्षों को साझा किया। श्रोताओं में मुख्य रूप से सभी नीति निर्माता, विभागाध्यक्ष, कुलपति या उनके प्रतिनिधि शामिल थे। कार्यक्रम में राज्य भर के विभिन्न शोध संस्थानों के वैज्ञानिकों ने भाग लिया।

राज्यपाल ने शिमला के सरस्वती विद्या मन्दिर पाठशाला के विद्यार्थियों के साथ संवाद किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने शिमला शहर के विकास नगर स्थित सरस्वती विद्या मंदिर पाठशाला के विद्यार्थियों के साथ संवाद करते हुए उन्हें राष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानियों से संबंधित पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी।

राज्यपाल विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम के तहत सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल पहुंचे और नौवीं कक्षा के विद्यार्थियों के बीच एक शिक्षक के रूप में कक्षा का संचालन किया। राज्यपाल ने विद्यार्थियों से अवकाश के दिनों में बिताये गये समय और पर्यावरण के प्रति उनकी जिम्मेदारी, वृक्षारोपण और समाचार पत्र पढ़ने इत्यादि के बारे में उनकी रुचि से संबंधित कई प्रश्न भी पूछे।

उन्होंने कहा कि पुस्तकें हमारी बौद्धिक संपत्ति और विरासत हैं। यह हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न विषयों पर कई पुस्तकें उपलब्ध हैं, और उनसे मित्रता करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अच्छी पुस्तकों को घर में जरूर स्थान दें और पुस्तकों के पठन पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने प्रत्येक विद्यार्थी को पुस्तकें भेंट की और पत्र

भेजकर पुस्तकों से अर्जित ज्ञान के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकें विद्यार्थियों को इसलिए दी गई हैं, ताकि उनमें पढ़ने की आदत विकसित हो सके।

इसके पश्चात, राज्यपाल ने स्कूल के शिक्षकों से भी संवाद किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को पुस्तक मेलों आदि में ले जाने की व्यवस्था की जाए ताकि उनमें पुस्तकों के प्रति रूचि पैदा हो सके। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को भी यह विषय माता-पिता के समक्ष रखना चाहिए।

करोड़ों की घोषणाएं कर जनता को गुमराह कर रहे मुख्यमंत्री:हर्षवर्धन

शिमला/शैल। हिमाचल की भाजपा सरकार साढ़े चार वर्षो के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। शिमला में पत्रकार वार्ता को

सम्बोधित करते हुए कांग्रेस विधायक दल के उपनेता व प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के चेयरमेन हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए हर दिन करोड़ों की घोषणाएं कर रहे है।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा की डब्बल इंजन की सरकार राज्य के लिए केन्द्र से कोई भी आर्थिक पैकेज लाने में पुरी तरह विफल साबित हुई है जबकि चुनावों के समय भाजपा नेता डब्बल इंजन सरकार का राग अलापते रहते थे। राज्य सरकार आज तक केन्द्र से राहत के तौर पर प्रदेश के लिए फुटी कौड़ी भी नहीं ला सकी।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की मांगों के प्रति असंवेदनशील है। कर्मचारियों के भर्ती के सभी मामलें उच्च न्यायालय में लटके हुए हैं। राज्य में कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर संघर्ष कर रहे है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद कैडर के सभी कर्मचारी कई दिनों से हड़ताल पर है जिससे पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे है, परन्तु राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने कहा कि NRHM के कर्मचारी भी हड़ताल पर है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के पैंशनरों को अभी तक छठे वेतन आयोग के एरियर की भुगतान नहीं किया गया है।

हर्षवर्धन चौहान ने राज्य सरकार से अपने साढ़े चार वर्षो के कार्यकाल की कारगुजारियों पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है।

हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार जानबूझ कर नगर निगम चुनावों को टाल रही हैं क्योंकि भाजपा को इन चुनावों में अपनी हार स्पष्ट नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा को अपनी सरकार की लोकप्रियता पर इनता विश्वास है तो समय पर नगर निगम शिमला के चुनाव क्यों नहीं करवाए।

नौणी विवि के वैज्ञानिक ने जीता ISAF गोल्ड मेडल

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के सिल्वीकल्चर

एवं एग्रोफोरेस्ट्री विभाग के प्रधान वैज्ञानिक (वानिकी/कृषि वानिकी) डॉ. डीआर भारद्वाज को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री (आईएसएएफ) के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इसी महीने केन्द्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में आयोजित इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री सोसायटी की कार्यकारी परिषद की बैठक के दौरान घोषित किया गया।

डॉ. भारद्वाज को शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में 27 वर्षो से अधिक का अनुभव है। इस दौरान उन्होंने 37 छात्रों को कृषि वानिकी और वनपालन के क्षेत्र में एक प्रमुख सलाहकार के रूप में मार्गदर्शन किया है। उनके पास कई शोध उपलब्धियां हैं जिनमें हिमालयी क्षेत्र की कई वृक्ष प्रजातियों के प्रसार और वृक्षारोपण प्रौद्योगिकी का विकास शामिल है। उन्होंने हिमाचल में महत्वपूर्ण खाद्य बांस प्रजातियों पर सफलतापूर्वक कार्य किया है। कृषक समुदाय के बीच इन प्रजातियों की काफी मांग है। प्रयोगों के आधार पर, राज्य की विभिन्न कृषि-जलवायु परिस्थितियों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली बांस की प्रजातियों की भी पहचान, डॉ भारद्वाज द्वारा की गई है। उनके द्वारा राज्य के लिए कई कृषि वानिकी मॉडल भी विकसित किए गए हैं। उत्तर-पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र की वृक्ष प्रजातियों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं और हिमालयी क्षेत्र के चारे के पेड़ और बांस की प्रजातियों का मूल्यांकन, उनके पोषण मूल्य, चारे और ईंधन की लकड़ी के उत्पादन के लिए किया गया है।

नौणी विवि के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल और विश्वविद्यालय के सभी संकाय और छात्रों ने डॉ भारद्वाज को उनकी उपलब्धि और विश्वविद्यालय और राज्य का नाम रोशन करने के लिए बधाई दी।

इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोफोरेस्ट्री की स्थापना 1998 में कृषि वानिकी के क्षेत्र में बुनियादी, अनुप्रयुक्त और रणनीतिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी। सोसायटी का उद्देश्य कृषि वानिकी से संबंधित ज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और कृषि वानिकी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले संगठनों के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करना है।

राज्यपाल ने कुल्लू बस दुर्घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया

शिमला/शैल। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कुल्लू जिला के शैंशर के निकट हुई बस दुर्घटना पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है।

अपने शोक संदेश में राज्यपाल ने ईश्वर से मृतकों को आत्मिक शांति प्रदान करने की प्रार्थना और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की।

मुख्यमंत्री ने बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को बधाई दी

शिमला/शैल । मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने 10वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों की मैरिट सूची में लड़कियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपना स्थान बनाया है, जिसके लिए वे बधाई की पात्र हैं। उन्होंने सभी उर्त्तीण विद्यार्थियों से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे भी कड़ी मेहनत करने का आहवान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज का काम जल्द शुरू होगा

शिमला/शैल। रेल मंत्री ने अम्ब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर पर फुट ओवर ब्रिज के निर्माण का आदेश दिया है। फुट ओवर ब्रिज, स्टेशन को जामा मस्जिद से जोड़ेगा और रेलवे स्टेशन से मस्जिद तक पहुंच को आसान बनाएगा। निर्माण के लिए निविदा खोल दी गई है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 1 जून, 2022 को रेल मंत्रीअश्विनी वैष्णव से ओवर ब्रिज निर्माण के लिए अनुरोध किए जाने के बाद यह आदेश जारी किया गया है।

विभागीय परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 13 जुलाई से

शिमला/शैल। भारतीय प्रशासनिक सेवा, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और हिमाचल प्रदेश वन सेवा के अधिकारियों, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और हिमाचल में कार्यरत अन्य सभी राजपत्रित एवं पात्र अधिकारियों के लिए विभागीय परीक्षाएं 19 से 28 सितंबर तक आयोजित की जाएंगी। इन परीक्षाओं के लिए पात्र अधिकारियों से 13 जुलाई से 16 अगस्त तक मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

शिमला के फेयरलांज स्थित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव नीरज सूद ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद आवेदन की विंडो स्वत: ही बंद हो जाएगी। उन्होंने बताया कि संबंधित विभागों के अनुमोदन के बाद ही प्रार्थी का आवेदन मान्य होगा और ये विभाग 22 अगस्त तक ही प्रार्थी का अनुमोदन कर सकेंगे। इसके बाद विभागाध्यक्ष की विंडो भी बंद हो जाएगी और प्रार्थियों के प्रवेश पत्र स्वत: ही मानव संपदा साइट पर प्रदर्शित हो जाएंगे।

बोर्ड के सचिव ने बताया कि विभागीय परीक्षाओं में भाग लेने के इच्छुक पात्र अधिकारियों की सुविधा के लिए वित्तीय प्रशासन पेपर-1 का आयोजन शिमला के अलावा मंडी और धर्मशाला में भी किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया और परीक्षा की समय सारिणी हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) की वेबसाइट हिपाशिमला डॉट एनआईसी डॉट इन hipashimla.nic.in. पर उपलब्ध करवा दी गई है।

भूजल उपयोगकर्ता 31 अगस्त तक करवाएं पंजीकरण

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी कि हिमाचल प्रदेश में सभी मौजूदा भूजल उपयोगकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन का विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम 2005 की धारा 8 के तहत 31 अगस्त, 2022 तक अपने मौजूदा भूजल संरचनाओं को फॉर्म-4 और 4-ए पर www.emerginghimachal. hp.gov.in या हिमाचल प्रदेश भूजल प्राधिकरण के पोर्टल www.hpiph.org के माध्यम से पंजीकृत करवाना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भूजल के सभी मौजूदा उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाएं व पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए www-.emerginghimachal.hp.gov.in or www.hpiph.org. पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 31 अगस्त, 2022 या उससे पहले करें, उसके पश्चात भूजल प्राधिकरण के पोर्टल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और 31 अगस्त, 2022 के बाद किसी भी आवेदन पर विचार नहीं लिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि इसके उपरांत मौजूदा टयूब बेल, बोर वेल और सक्रिय हैंड पम्प (घरेलू, सिंचाई, वाणिज्यक और औद्योगिक उद्देश्यों) जो हिमाचल प्रदेश ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी शिमला के साथ पंजीकृत नहीं हैं, के अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं के खिलाफ हिमाचल प्रदेश भूजल (विकास और प्रबंधन के विनियमन और नियंत्रण) अधिनियम, 2005 और नियम, 2007 की विभिन्न धाराओं के तहत उचित कार्यवाई की जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

लोक सेवा आयोग को लेकर आये उच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना कब होगी? उठने लगा है सवाल

- सर्वोच्च न्यायालय 2013 में ऐसे निर्देश पंजाब हरियाणा के संद्धर्भ में दे चुका है
- 2018 में सदस्यों के 2 पद सृजित करके एक ही क्यों भरा गया?
- सरकार के इसी कार्यकाल में तीसरा अध्यक्ष नियुक्त करने की स्थिति क्यों बनी
- आयोग में परीक्षाओं के परिणाम निकालने में पहले की अपेक्षा अब देरी क्यों हो रही है

शिमला/शैल। प्रदेश लोकसेवा आयोग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा के मुद्दे हैं सरकार द्वारा आयोग के सदस्यों को पैन्शन देने का फैसला लेना। इसी के साथ आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे के. एस. तोमर की उच्च न्यायालय में याचिका जिसमें 300 और 250 पैन्शन देने के 1974 में किये गये प्रावधान को आज के संद्धर्भ में संवैधानिक पद के साथ क्रूर मजाक करार देते हुये इसे सम्मान करने का आग्रह इन्हीं मुद्दों के साथ उच्च न्यायालय द्वारा जनवरी 2020 में सरकार को दिये गये निर्देशों की आज तक अनुपालना न हो पाना इन निर्देशों में उच्च न्यायालय ने लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया और नियम बनाने के निर्देश/ उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है The Court said that it hopes that the State of H.P. must step in and take urgent steps to frame memorandum of Procedure, administrative guidelines andparameters for the selection and appointment of the Chairperson and Members of the Commission, so that the possibility of arbitrary appointments is eliminated. उच्च न्यायालय ने यह निर्देश इसलिए दिये कि जो याचिका अदालत में आयी थी उसमें मीरा वालिया की नियुक्ति को अवैध करार देने के आग्रह के साथ ही एक तय प्रक्रिया और नियम बनाये जाने की गुहार लगाई गयी थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी 2013 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से अपील में शीर्ष अदालत के पास पहुंचे एक मामले में दिये गये थे। सर्वोच्च न्यायालय के इन निर्देशों पर शायद इसीलिये अमल नहीं किया गया कि इसे पंजाब हरियाणा का ही मामला मान लिया गया। लेकिन अब जब प्रदेश उच्च न्यायालय से भी ऐसे ही निर्देश आ चुके हैं तब भी प्रदेश सरकार द्वारा उसकी अनुपालना न किया जाना जयराम सरकार की नीयत और नीति दोनों पर ही कई गंभीर सवाल खड़े कर देता है। स्मरणीय है कि जबसे प्रदेश लोकसेवा आयोग का संविधान की धारा 315 के तहत गठन हुआ है तब से लेकर आज तक इसमें सेना के लैजनरल से लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव डीजीपी और पत्रकार तक अध्यक्ष रह चुके हैं। सदस्यों के नाम पर भी आई. ए.एस. अधिकारियों से लेकर इंजीनियर वकील विभागों के उप निदेशक और पत्रकार तक इसके सदस्य रह चुके हैं।

ऐसा इसीलिये हुआ है क्योंकि आज तक सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति के लिये कोई निश्चित प्रक्रिया और नियम ही नहीं बन पाये हैं। शायद पूरे देश में ऐसा ही है इसलिये जब पंजाब हरियाणा का मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था तब ऐसी ही छः याचिकाएं शीर्ष अदालत के पास लंबित थी। सर्वोच्च न्यायालय ने तब इसका कड़ा संज्ञान लेते हुए यह कहा था कि लोकसेवा आयोग राज्य की शीर्ष प्रशासनिक सेवाओं के लिये उम्मीदवारों का चयन करते हैं परंतु उनके अपने ही चयन के लिये कोई प्रक्रिया और नियम न होना खेद का विषय है। जबकि इनकी नियुक्ति तो राज्यपाल करता है परंतु इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। पर उसके लिये भी इनके खिलाफ आयी शिकायत की जांच सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी। सर्वोच्च न्यायालय की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति उन्हें हटा सकता है। या विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ऐसा कर सकती है। इसलिये इनकी नियुक्ति के लिये भी नियम और प्रक्रिया होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि सदस्य बनने के लिये सरकार के वित आयुक्त जितनी योग्यता होनी चाहिये। प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को ही आगे बढ़ाते हुये जनवरी 2020 में जयराम सरकार को निर्देश दिये थे कि वह तुरन्त प्रभाव से यह नियम बनाये जो आज तक नहीं बने हैं।

यहां यह भी समरणीय है कि जयराम सरकार ने जब सत्ता संभाली थी तब लोकसेवा आयोग में सदस्यों के दो पद सृजित किये गये परंतु उनमें से भरा एक ही। बल्कि आज तक यह पद भरा नहीं गया है। यहां यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब दूसरा पद भरना ही नहीं था तो उसको सृजित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जयराम सरकार के कार्यकाल में शायद अध्यक्ष की नियुक्ति भी थोड़े-थोड़े समय के लिये ही होती रही है। इसमें भी यह सवाल उठते रहे हैं कि क्या सरकार को ऐसा व्यक्ति ही नहीं मिलता रहा जो पूरे छः वर्ष के लिये अध्यक्ष रह पाता। इसमें भी सरकार की नीयत पर सवाल उठते रहे हैं। क्योंकि सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही फिर अध्यक्ष की नियुक्ति की जायेगी। एक कार्यकाल में तीन बार अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाना एक तरह से संस्थान की प्रतिष्ठा को भी सवालों में लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि इससे संस्थान की कार्य संस्कृति प्रभावित हुई है। आज आयोग द्वारा ली जा रही परीक्षाओं के परिणाम निकालने में इतना समय लगाया जा रहा है जो पूर्व में नहीं लगता था। आज छः माह से लेकर एक वर्ष तक परिणाम नहीं आ रहे हैं। चर्चा है कि एच.पी.सी.एल. में ए.ई. की परीक्षा को करीब एक वर्ष हो रहा है और परिणाम नहीं आया है। एच.ए.एस. के परिणाम में ही शायद माह का समय लग गया है। आम आदमी पर इस देरी का क्या असर पड़ेगा इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसा इसीलिए हो रहा है कि सरकार उच्च न्यायालय के निर्देशों के बावजूद नियम बनाने को तैयार नहीं है। शायद अगले अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद ही इस बारे में विचार किया जायेगा। जिस ढंग से पैन्शन का फैसला लिया गया है उससे स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री को सलाह नहीं मिल रही है। क्योंकि पैन्शन का फैसला तो आयोग के गठन के साथ ही ले लिया गया था। 1974 के 300 रूपये की आज क्या कीमत होगी यह कोई भी अनुमान लगा सकता है। फिर ब्रिगेडियर एल. एस. ठाकुर को अदालत पैन्शन का लाभ दे ही चुकी है। इसी के आधार पर डॉ. मानसिंह, प्रदीप चौहान, मोहन चौहान अदालत गये थे। उच्च न्यायालय ने इन के हक में फैसला दिया था। सरकार जिस की अपील में सर्वोच्च न्यायालय गयी हुई है। शीर्ष अदालत में मामला अभी तक लंबित है। ऐसे में क्या अभी 1974 के प्रावधान को जनता के सामने रखे बिना पैन्शन का फैसला लिया जाना चाहिये था। आज आर्थिक संकट के दौर में सारी स्थिति जनता में स्पष्ट किये बिना फैसला लेना सही ठहराया जा सकता है क्या यह मुख्यमंत्री के सलाहकारों पर प्रशन नहीं है।

आखिर क्यों नहीं बढ़ रही है आप शिक्षा के मुद्दे से आगे

शिमला/शैल। आम आदमी पार्टी इकाई ने प्रदेश विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान कर रखा है। यह ऐलान पंजाब की जीत के बाद किया गया था। आप के केंद्रीय नेता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दो-दो बार हिमाचल आ चुके हैं। बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी केजरीवाल के साथ आ चुके हैं। 400 लोगों की नई प्रदेश इकाई भी घोषित हो चुकी है। केंद्रीय नेताओं की रैलियों में दिल्ली की तर्ज पर हिमाचल में भी अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधायें देने का वायदा किया गया है। केन्द्रिय नेताओं के इस आश्वासन के बाद प्रदेश इकाई शिक्षा व्यवस्था को चुनावी सफलता का एक बड़ा मंत्र मानकर लगातार इस के जाप में लग गयी है। शिक्षा और स्कूलों से जुड़े आंकड़े परोसे जा रहे हैं। पंजाब में भी शिक्षा और स्वास्थ्य को बड़ा मुद्दा बनाकर प्रचारित किया गया था। दिल्ली मॉडल के आकर्षण में पंजाब में 92 सीटें जीतकर इतिहास रच चुके हैं। लेकिन दिल्ली मॉडल और चुनावी वायदों पर पंजाब में कितना अमल हो पाया है और पार्टी की लोकप्रियता कितनी बड़ी है इसका खुलासा अब चार माह बाद ही संगरूर लोकसभा का उपचुनाव हार कर सामने आ चुका है। मुख्यमंत्री अपने घर के बूथ पर भी बढ़त नहीं दिला पाये हैं। इस परिदृश्य में हिमाचल में आप का परफॉरमेन्स क्याा और कैसा रहेगा अब इस पर चर्चा चलनी शुरू हो गयी है। अभी पंजाब का बजट आ चुका है और उसमें किये गये वादे भी सामने आ चुके हैं। अभी जून में ही आरबीआई देश के 10 राज्यों की सूची जारी कर चुका है जिनकी वित्तीय स्थिति अति गंभीर है। इस स्थिति के चलते पंजाब में किये गये वायदों को पूरा करना तो दूर बल्कि सरकार को चलाये रखना भी कठिन हो जायेगा। क्योंकि पंजाब का आउटस्टैंडिंग कर्ज ही जीडीपी के 200 प्रतिशत से भी कहीं ज्यादा है। हिमाचल का कर्ज भी 87प्रतिशत तक पहुंच चुका है। ऐसे में प्रदेश की आर्थिक स्थिति का संज्ञान लिये बिना शिक्षा स्वास्थ्य या और भी किसी अन्य विषय में बात करना बेमानी हो जाता है। क्योंकि आगे कर्ज लेना भी आसान नहीं रह जायेगा। इसलिये आप की प्रदेश इकाई द्वारा शिक्षा स्वास्थ्य के जाप से आगे न बढ़ना अपरोक्ष में भाजपा की ही मदद करने का प्लान माना जा रहा है।